भाजपा विधायकों से भी पूछा जाएगा पंचायत चुनाव में हार का कारण

मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष व संगठन महामंत्री की बैठक में समीक्षा का दायरा जिला संगठन से आगे बढ़ाने पर विचार हुआ

जयपुर, 21 नवम्बर। राजस्थान के पंचायत चुनावों में भाजपा को मिले करारे झटके के बाद, पार्टी में हार के कारणों की तलाश और जवाबदेही तय करने की कवायद तेज हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस की मजबूत वापसी ने भाजपा के सत्ता और संगठन दोनों की चिंता बढ़ा दी है। यही वजह है कि अब

- **भाजपा ने पंचायत चुनाव के टिकट वितरण में विधायकों व विधानसभा प्रत्याशियों को काफी हद तक फ्री हैंड दिया था। अब उनसे पूछा जाएगा कि जब उनकी पसंद के प्रत्याशी थे तो अपेक्षित सफलता क्यों नहीं मिली।**

हार की समीक्षा का दायरा जिला संगठन से आगे बढ़ाकर विधायकों और विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे नेताओं तक पहुंच गया है। मुख्यमंत्री निवास (सीएमआर) में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और संगठन महामंत्री अजेय कुमार के बीच मंथन के बाद, देर शाम भाजपा मुख्यालय में भी महत्वपूर्ण बैठक हुई।

भाजपा मुख्यालय पहुंचे वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ चुनाव परिणामों और संगठनात्मक



राजस्थान के पंचायत चुनावों में भाजपा को मिली हार के बाद शनिवार को प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, संगठन महामंत्री अजेय कुमार सहित अनेक भाजपा नेता मौजूद थे।

स्थिति पर चर्चा की। बैठक में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, संगठन महामंत्री अजेय कुमार, प्रदेश महामंत्री श्रवण बगड़ी, मिथिलेश गौतम, सरदार अजय पाल सिंह सहित अनेक भाजपा नेता मौजूद रहे।

भाजपा संगठन ने सभी जिला अध्यक्षों से अपने-अपने क्षेत्रों में चुनाव परिणामों और हार के कारणों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। खास बात यह है कि समीक्षा के दायरे में स्थानीय विधायक और विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे नेता भी शामिल किए जा रहे हैं।

दरअसल, पंचायत चुनाव में टिकट वितरण के दौरान विधायकों और विधायक प्रत्याशियों को काफी हद तक फ्री हैंड दिया गया था। उम्मीदवारों के चयन में उनकी पसंद और सिफारिशों को प्राथमिकता मिली थी। ऐसे में अब पार्टी यह जानना चाहती है कि जिन क्षेत्रों में स्थानीय नेताओं ने अपनी पसंद के उम्मीदवार मैदान में उतारे, वहां पार्टी को अपेक्षित सफलता क्यों नहीं मिली।

पंचायत चुनाव के नतीजों ने भाजपा के भीतर सत्ता और संगठन के बीच तालमेल को लेकर उठ रहे सवालों को फिर चर्चा में ला दिया है। चुनाव से पहले कई क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा, जनप्रतिनिधियों की नाराजगी और स्थानीय स्तर पर सुनवाई नहीं होने की शिकायतें सामने आती रही थीं। अब संगठन इन पहलुओं को भी समीक्षा का हिस्सा बना सकता है।

सदस्य चुनावों के बाद अब जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव भाजपा के लिए अगली बड़ी राजनीतिक परीक्षा होंगे। जिन जिलों और पंचायत समितियों में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, वहां निर्दलीयों और छोटे दलों की भूमिका निर्णायक हो सकती है। भाजपा संगठन स्थानीय समीकरणों के आधार पर समर्थन जुटाने की रणनीति बना रहा है।

आईआईटी और आईटीआई दोनों देश की अमानत हैं - मोदी

लखनऊ, 21 नवंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि देश के छात्र ही राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत और भविष्य हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) हो या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), संस्थानों में पढ़ ने वाले युवा देश की असली संपत्ति हैं और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका बेहद अहम है।

प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित पांचवें राष्ट्रीय कौशल दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने देशभर के युवाओं को संबोधित किया और कौशल विकास को राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण आधार बताया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जिस उत्साह और उम्मीदों के साथ वे आईआईटी के छात्रों के बीच पहुंचे थे, उसी ऊर्जा और जोश के साथ आईटीआई के विद्यार्थियों के बीच आए हैं। उन्होंने कहा कि चाहे आईआईटी हो या आईटीआई हो, मेरे लिए तो यही मेरे देश की अमानत है।

ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को समर्थन, चीन की रणनीति का हिस्सा था

अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार, भारत के प्रभाव को कम करने के लिए, चीन सीमा पर दबाव व आर्थिक प्रतिबंधों का प्रयोग करता है

- **अमेरिका के विशेषज्ञों के अनुसार, चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए, वॉशिंगटन व नई दिल्ली को खुफिया जानकारी, समुद्री मामलों व विनिर्माण के क्षेत्र में गहरा सहयोग करना चाहिए।**

वॉशिंगटन डीसी, 21 नवंबर। अमेरिकी कांग्रेस के एक पैनल ने अपनी नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन का सैन्य समर्थन, "भारत के उदय को दबाने" की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा था। पैनल ने चेतावनी दी है कि बीजिंग, नई दिल्ली के रणनीतिक प्रभाव को सीमित करने के लिए सीमा पर सैन्य दबाव, आर्थिक प्रतिबंधों और समुद्री विस्तार का इस्तेमाल कर रहा है।

यूएस-चीन आर्थिक और सुरक्षा समीक्षा आयोग (यूएससीसी) ने चीन के बढ़ ते क्षेत्रीय प्रभाव का मुकाबला करने के लिए, वाशिंगटन और नई दिल्ली के बीच खुफिया जानकारी, समुद्री मामलों और विनिर्माण के क्षेत्र में गहरे सहयोग का आव्हान किया है। रिपोर्ट में एशिया में शक्ति संतुलन तय करने और बीजिंग की रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं को रोकने में भारत के महत्व पर भी जोर दिया गया है।

"चीन का दूसरा मोर्चा: भारत और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी रणनीति का भविष्य" शीर्षक वाले एक अध्याय में, कॉंग्रैशनल कमीशन ने कहा है कि इस्लामाबाद के साथ बीजिंग की बढ़ ती सुरक्षा साझेदारी ने भारत के लिए टू-फ्रंट वॉर की संभावना को एक गंभीर चिंता बना दिया है। मई 2025 के भारत-पाकिस्तान संघर्षका जिक्र करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि कैसे चीन, सीधे तौर पर लड़ाई में शामिल हुए बिना, संकट के समय पाकिस्तान की मदद कर सकता है।ष्कमीशन के अनुसार, इस तरह का समर्थन पाकिस्तान के साथ भविष्य में होने वाले किसी भी टकराव में भारत की सैन्य योजना को जटिल बना सकता है। इसमें आगे कहा गया है कि इस्लामाबाद के साथ चीन की विकसित होती सैन्य साझेदारी ने नई दिल्ली के लिए टू-फ्रंट वॉर की स्थिति को एक अत्यंत गंभीर चिंता का विषय बना दिया है।

फरवरी में ईरान पर हमला करने का फैसला राष्ट्रपति ट्रंप का था - वैंस

उपराष्ट्रपति के कथन से अमेरिकी प्रशासन में मतभेद उभर कर सामने आए

वॉशिंगटन, 21 नवंबर। अमेरिका और ईरान के बीच जारी सैन्य संघर्ष को लेकर अमेरिकी प्रशासन के भीतर मतभेद सामने आने लगे हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने शुक्रवार को ईरान पर अमेरिकी हमले को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का खुलकर समर्थन करने से परहेज किया। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए दोबारा सैन्य हमला करने की अनुमति देते तो उन्होंने सीधे जवाब देने से इनकार कर दिया। वेंस ने कहा कि फरवरी में ईरान पर हमला करने का फैसला राष्ट्रपति ट्रंप का था और उनका काम राष्ट्रपति का समर्थन करना है।

- **राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वे वैंस के चुनावी विश्लेषण से नाराज नहीं हैं। वे चाहते थे कि वैंस यह स्वीकार करें कि ईरान पर हमले जरूरी थे और जरूरत पड़ने पर वह भी यही फैसला लेते।**

पाकिस्तानी मीडिया "जिओ न्यूज" के अनुसार, वाइट हाउस में डॉनल्ड ट्रंप के साथ आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेंस का यह बयान ऐसे समय आया है, जब ईरान के साथ जारी संघर्ष को लेकर अमेरिका में राजनीतिक बहस तेज हो रही है। खासकर मिडटर्म चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को मिली हार के बाद युद्ध की रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं।

जेडी वेंस ने हाल ही में सोशल मीडिया पर रिपब्लिकन पार्टी की चुनावी हार का विश्लेषण करते हुए ईरान युद्ध को एक बड़ी वजह बताया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका को इस संघर्ष से बाहर निकलने की जरूरत है। उनके इस बयान को राष्ट्रपति ट्रंप की विदेश नीति से दूरी बनाने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। वेंस ने अपनी पोस्ट में लिखा था कि पार्टी की हार इसलिए हुई, क्योंकि युद्ध जारी था। यदि कोई यह मानता है कि अगले छह वर्षों के लिए सीनेट में नुकसान उठाना इस युद्ध की सही कीमत थी तो उसे खुलकर यह तर्क देना चाहिए।

उनके इस बयान के बाद अमेरिकी राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई कि क्या उपराष्ट्रपति ईरान को लेकर ट्रंप की सैन्य रणनीति से पूरी तरह सहमत नहीं हैं।

राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि वह वेंस के चुनावी विश्लेषण से नाराज नहीं हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि उपराष्ट्रपति की बात में एक महत्वपूर्ण पहलू छूट गया है। ट्रंप चाहते थे कि वेंस यह स्वीकार करें कि ईरान पर हमले जरूरी थे और जरूरत पड़ने पर वे भी यही फैसला लेते। ट्रंप ने कहा कि उनके साथ काम करने वाले लोगों को अपनी राय रखने का पूरा अधिकार है। हालांकि, उन्होंने ईरान को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि वे ईरान को अच्छी तरह जानते हैं और वहां के नेतृत्व पर भरोसा नहीं किया जा सकता।

नये नियमों से ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वाले रेफरेंस पर सुनवाई करते हुए दिए।

अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि किसी अभियुक्त को दिया गया पैरोल उसकी सजा का निलंबन या लघुकरण नहीं है। यह सशर्त रिहाई है जो केवल सजा भुगतने के तरीके को बदलती है। पैरोल नियम, 2021 के नियम 10 के तहत, पैरोल पर बिताई गई अवधि को कारावास भुगतना ही माना जाता है।

हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष पैरोल से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान यह सामने आया था कि किसी कैदी की ओर से पैरोल के लिए पेश आवेदन पर विचार करते समय क्या यह देखा जाएगा कि जब उसे सजा सुनाई गई थी, उस समय लागू होने वाले साल 1958 के नियम लागू होंगे या अब उनके स्थान पर लागू होने वाले साल 2021 के पैरोल नियम।

इसके साथ ही, अदालत के सामने यह भी बिंदु आया कि क्या पैरोल प्रदान करना बीएनएसएस के तहत सजा के अस्थायी निलंबन के समान है, इन दोनों बिंदुओं पर अलग-अलग कोर्ट के अलग-अलग न्यायिक दृष्टिकोण हैं। ऐसे में मामला फुल बेंच में तय करने के लिए भेजा गया था।

हरिद्वार : नमामि गंगे घाट पर मु.मंत्री योगी की मां का अंतिम संस्कार

हरिद्वार, 21 नवंबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी का शनिवार को हरिद्वार के नमामि गंगे घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मुख्यमंत्री योगी के सबसे छोटे भाई महेन्द्र सिंह बिष्ट ने मुखाग्नि दी। मां को अंतिम विदाई देते समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद भावुक नजर आए। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े और वह बार-बार आंसू पोंछते दिखाई दिए।

- **मां को अंतिम विदाई देते समय बेहद भावुक हुए मुख्यमंत्री की आंखों से आंसू छलक पड़े।**

सावित्री देवी का पार्थिव शरीर शनिवार सुबह उनके पैतृक गांव पंचूर से हरिद्वार स्थित नमामि गंगे घाट पहुंचा। यहां अंतिम दर्शन के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई बड़े राजनीतिक नेता, मंत्री, सांसद, विधायक और संत-महात्मा पहुंचे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सावित्री देवी को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि के बाद पूरे राजकीय सम्मान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अंतिम संस्कार की प्रक्रिया संपन्न कराई गई।

इस दौरान घाट पर सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धांजलि देने के लिए आए लोगों की भारी भीड़ के कारण घाट पर दबाव बढ़ गया। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस और प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी।

कोर्ट की डिक्री से...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

स्पष्ट किया है कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त छूट का अर्थ यह नहीं है कि सरकारी नौकरी में तलाकशुदा महिला आरक्षण का लाभ लेने के लिए कानूनी रूप से सत्यापन योग्य प्रमाण देने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

अदालत ने माना कि जनजातीय समुदायों में विवाह विच्छेद के लिए पारंपरिक रीति-रिवाज हो सकते हैं। हालांकि, ऐसे रीति-रिवाजों का अस्तित्व, उनकी प्राचीनता, लागू होने की स्थिति और निर्धारित प्रक्रिया सक्षम न्यायालय में साक्ष्यों के आधार पर साबित करनी होगी।

यह मामला सुनीता मीणा और संगीता के मामलों में दो अलग-अलग खंडपीठों के परस्पर विरोधी फैसलों के कारण कानूनी बिंदु तय करने के लिए फुल बेंच में भेजा गया था। इसमें मुख्य सवाल यह था कि क्या कोई एसटी महिला भर्ती आवेदन की अंतिम तिथि से पहले अदालत से तलाक की डिक्री प्राप्त किए बिना परंपरागत तलाक के आधार पर तलाकशुदा श्रेणी का लाभ ले सकती है।

एंबुलैंस और पिकअप की टक्कर में पांच की मौत

बाराबंकी, 21 नवंबर। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर शनिवार सुबह एंबुलैंस और पिकअप की भीषण टक्कर में पांच लोगों की मौत हो गई।

हादसा सुबेहा थाना क्षेत्र के गेरांवा गांव के पास सुबह करीब 6:30 बजे हुआ। एंबुलैंस जयपुर से एक शव लेकर पश्चिम बंगाल जा रही थी। इसी दौरान उसकी पिकअप से टक्कर हो गई। हादसे में एंबुलैंस सवार पांचों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

पुलिस के अनुसार, अजय और हरिओम एंबुलैंस के चालक थे। हादसे के बाद पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।

प्रधानमंत्री ने 19.7 किमी लंबा "नीतीश सेतु" बिहार की जनता को समर्पित किया

छः लेन के इस पुल के निर्माण पर 4,988 करोड़ रूपए खर्च हुए हैं

पटना, 21 नवंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को बिहार दौरे पर पहुंचे। पटना हवाई अड्डे पर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनका स्वागत किया। इस दौरान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे।

- **पटना के केच्ची दरगाह को वैशाली जिले के बिदुपुर से जोड़ने वाले इस पुल से उत्तर व दक्षिण बिहार के बीच संपर्क व्यवस्था सुगम होगी व आम जनता को बहुत राहत मिलेगी।**

हवाई अड्डे से प्रधानमंत्री सीधे वैशाली जिले के राघोपुर पहुंचे, जहां उन्होंने नवनिर्मित नीतीश सेतु का उद्घाटन किया। करीब 19.7 किलोमीटर लंबे इस छह लेन पुल को उन्होंने बिहार की जनता को समर्पित किया।

प्रधानमंत्री ने अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में स्थित पुल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सेतु से गमछा लहराकर वहां मौजूद लोगों का अभिवादन किया। इसके बाद विधिवत उद्घाटन किया।

इस अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर) सैयद अता हसनैन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केन्द्रीय मंत्री चिराग पासवान और उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी सहित, कई गणमान्य लोग उपस्थित थे।

नीतीश सेतु पटना के कच्ची दरगाह को वैशाली जिले के बिदुपुर से जोड़ता है। इसके निर्माण से दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार के बीच सड़क संपर्क और मजबूत होगा। यह एक्स्ट्राडोज्ड केबल-स्टे तकनीक से निर्मित छह लेन का पुल है। इसके निर्माण पर 4,988.40 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं।

करीब 19.7 किलोमीटर लंबी इस परियोजना में 9.7 किलोमीटर लंबा मुख्य पुल और 10 किलोमीटर लंबी संपर्क सड़कें (एप्रोच रोड) शामिल हैं। यह पटना जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-22 स्थित कच्ची दरगाह को वैशाली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-322 स्थित बिदुपुर से जोड़ता है। पुल के शुरू होने से दोनों क्षेत्रों के बीच आवागमन सुगम होने के साथ ही उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच संपर्क व्यवस्था को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है।

नीट पेपर लीक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

यश यादव, मांगीवाल बिवाल, दिनेश बिवाल, विकास बिवाल, शुभम खैरनार, धनंजय लोखंडे, प्रह्लाद कुलकर्णी, तेजस हर्षद कुमार, डॉ. मनोज शिरुरे, शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर, मनीषा वाघमारे, मनीषा मंधारे, मनीषा संजय हवलदार और शेषराव बजरंग सूर्यवंशी शामिल हैं।

दादी के संस्कार में शामिल हुए कट्टरपंथी सांसद अमृतपाल

चंडीगढ़ , 21 नवंबर। एनएसए के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल शनिवार को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अपनी दादी चरण कौर के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अंतिम रस्मों के बाद पुलिस उन्हें बख्तरबंद गाड़ियों में फिर से असम ले गई।

सांसद अमृतपाल की दादी चरण कौर का 8 नवंबर को निधन हुआ था। अमृतपाल की पैरोल के चलते अभी तक उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया था। अमृतसर की अदालत ने कई शर्तों के आधार पर गत दिवस अमृतपाल को तीन घंटे की पैरोल दी थी। अमृतपाल को असम के डिब्रूगढ़ से अमृतसर लाने के खर्च की राशि दस लाख रुपये परिवार की तरफ से कोर्ट में जमा करवाई गई थी।

पंजाब पुलिस की एक टीम शुक्रवार रात अमृतपाल को लेकर दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंची थी। रातभर सेफ हाउस में रूकने के बाद अमृतपाल को शनिवार सुबह दिल्ली हवाई अड्डे से अमृतसर लाया गया। सुबह 8.30 बजे पुलिस टीम अमृतपाल को लेकर अमृतसर पहुंची। यहां तीन घंटे उन्हें सेफ हाउस में रखा गया। कोर्ट के आदेशानुसार अमृतपाल को उनके पैतृक गांव जल्लूपुर खेड़ा पहुंचाया गया। यहां पहुंचकर वह अपने घर गए जहां दादी की मृतक देह को नमन किया।

दिल्ली- एनसीआर में एक्यूआई 279 पर पहुंचा

नई दिल्ली, 21 नवंबर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर एक बार फिर चिंता बढ़ ाने लगा है। शनिवार की सुबह दिल्ली की हवा खराब श्रेणी में दर्ज की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, सुबह 7 बजे दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 279 रिकॉर्ड किया गया। वहीं, राजधानी के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर 300 के पार पहुंच गया, जहां हवा बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली के कुछ प्रमुख इलाकों में वायु गुणवत्ता की स्थिति बेहद चिंताजनक रही। एम्स में एक्यूआई 369 और चांदनी चौक में 365 दर्ज किया गया। इसके अलावा वजीरपुर में 332, आनंद विहार में 327, आईआईटी दिल्ली में 308 और बवाना में 304 एक्यूआई रिकॉर्ड किया गया। इन इलाकों में हवा बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है।

शिक्षा विभाग में 337 असिस्टेंट...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नोटिफिकेशन से पहले जारी कर दी गई थी।

रचिता माथुर की और से अदालत को बताया गया कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भर्ती एंड हॉस्पिटल केयर टेकर भर्ती के लिए विज्ञप्ति 12 मई 2022 को और 23 मई 2022 को जारी की गई थीं। इन भर्तियों में भी आर पी एस सी ने चयन प्रक्रिया में बदलाव किया और इंटरव्यू का अंक भार 10 प्रतिशत ही कर दिया था। उल्लेखनीय है कि 2021 की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में परीक्षा में मिले अंक का 40 प्रतिशत भार शैक्षिणक योग्यता को, 20 प्रतिशत अंक परीक्षा को और इंटरव्यू को 40 प्रतिशत अंक दिए जाने की प्रथा अपनायी जा रही थी, परंतु विज्ञप्ति में इस संदर्भ में कोई जानकारी स्पष्ट नहीं की गई थी। एकल पीठ के समक्ष डॉ रचिता माथुर व अन्य की ओर से कहा गया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2021 की चयन प्रक्रिया में अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लिया जाना ही शेष था, अभ्यर्थियों की परीक्षा हो चुकी थी व योग्यता का भी आंकलन किया जा चुका था। उनकी गुहार थी कि इंटरव्यू का अंक भार कुल अंक का केवल 10 प्रतिशत ही हो। एकल पीठ ने जब आर पी एस सी का रिकॉर्ड मंगवाया तो यह स्पष्ट हुआ कि आर पी एस सी जिन विशेषज्ञों को इंटरव्यू लेने के लिए बुला रही थी, उनके द्वारा दी गई सिफारिशें केवल एक सलाहकार या असिस्टेंट के तौर पर लिखी जा रही थीं और किस अभ्यर्थि को कैसे अंक दिए जा रहे थे, यह स्पष्ट नहीं था। यानी विशेषज्ञों की राय को अनसुना कर मनमाने तरीके से अंक दिए जा रहे थे। उल्लेखनीय है कि भर्ती में प्रकाशित इन 337 पदों के लिए करीब तीन हजार अभ्यर्थियों ने भाग लिया था परंतु इन्हें इंटरव्यू में कैसे अंक देकर मेरिट लिस्ट जारी की जा रही थी यह स्पष्ट नहीं था।

एकल पीठ ने इस धांधली को देखते हुए आदेश पारित किये थे कि आर पी एस सी 2021 की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में भी 2022 के नोटिफिकेशन के अनुसार इंटरव्यू का अंक भार 40 प्रतिशत से घटा कर, 10 प्रतिशत करे। गौरतलब है कि आर पी एस सी व शिक्षा विभाग ने इस फैसले के खिलाफ 2025 में ही अपील दायर की थी। सुनवाई के दौरान यह सामने आया कि आर पी एस सी ने 2022 की हॉस्पिटल केयर टेकर भर्ती और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भर्ती के इंटरव्यू में 10 प्रतिशत अंक दिए जाने का फैसला तभी लागू कर पाए, क्योंकि हॉस्पिटल केयर टेकर भर्ती की विज्ञप्ति उसी दिन जारी की गई थी, जिस दिन आर पी एस सी का इंटरव्यू में केवल 10 प्रतिशत अंक देने का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। दूसरी ओर, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भर्ती की विज्ञप्ति 12 मई 2022 को जारी करी गई थी और अभ्यर्थी परीक्षा में भाग लेने के लिए आवेदन भर रहे थे। इसलिए आर पी एस सी ने विज्ञप्तियों में संशोधन कर नए नियम को लागू कर लिया और अभ्यर्थियों के आवेदन भी मंगवा लिए। विभाग और आर पी एस सी का कहना था कि यह नियम 2021 की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में इसलिए लागू नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उस भर्ती परीक्षा की चयन प्रक्रिया काफी आगे बढ़ गई थी और नियम नहीं बदले जा सकते थे। इसलिए खंड पीठ ने एकल पीठ के आदेश को रद्द कर दिया। अब 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की खंड पीठ के आदेश पर मोहर भी लगा दी है।

अब 337 पदों को भरने का रास्ता तो खुल गया, परंतु यह पद आर पी एस सी द्वारा 2024 में जारी की गई मेरिट लिस्ट के आधार पर ही होंगे, जिसमें इंटरव्यू के दौरान कैसे अंक दिए गए है, यही सबसे बड़ा विवाद था।

गहलोत ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लिया, जहां इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था। वे अपना पक्ष रखने के लिए अंबिका सोनी, मुकुल वासनिक और अन्य वरिष्ठ सहयोगियों पर निर्भर हैं।

आज गहलोत जयपुर में थे और मीडिया को इंटरव्यू दे रहे थे। वे इस जीत का हिस्सा बनना चाहते थे और कह रहे थे कि यह एकजुट कांग्रेस पार्टी की सामूहिक कोशिशों का नतीजा है।

लेकिन सूत्रों का कहना है कि नई दिल्ली में पार्टी नेतृत्व इस बात को अच्छी तरह समझ गया है कि ये नतीजे भाजपा सरकार के खराब प्रदर्शन की वजह से आए हैं। अब कांग्रेस अपने नेताओं को कैसे तैनात करती है और अपनी टीम को कैसे फिर से व्यवस्थित करती है, यह इस बात को ध्यान में रखकर तय किया जाएगा कि आगामी चुनावों में पार्टी का नेतृत्व करने के लिए सबसे सही व्यक्ति कौन है।

'राधे, राधे, कमल खिला दे'...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वे भगवान कृष्ण के सच्चे भक्त हैं, तो मंदिर निर्माण के लिए "कार सेवा" में शामिल हों। हेमा मालिनी ने कहा कि पार्टी चाहती है कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण "उचित तरीके से वैसे ही हो, जैसे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया गया है।"

बैठक में "अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी" के साथ ही, एक नया नारा, "राधे-राधे, कमल खिला दे," भी दिया गया। इन नारों के जरिए, ब्रज की सांस्कृतिक पहचान को भाजपा के चुनाव चिह्न "कमल" से जोड़ने की कोशिश की गई।

माना जा रहा है कि कृष्ण जन्मभूमि का विवाद शायद वैसी तीव्र भावनाएं पैदा न कर पाए, जैसी कभी अयोध्या मामले में देखने को मिली थीं। खासकर शाही ईदगाह स्थल से जुड़ी कानूनी जटिलताओं और अयोध्या तथा काशी में मंदिर परियोजनाओं के पूरा होने के बाद। इसके बावजूद भाजपा इस मुद्दे पर डटी हुई है। इसके पीछे चुनाव से जुड़े कई उद्देश्य हैं। इनमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी के समर्थन को मजबूत करना शामिल है, जहां 2022 में पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा था। इसके अलावा, अखिलेश यादव की हाल की "सॉफ्ट हिंदुत्व" वाली राजनीति (जिसमें मंदिरों के दौरे और धार्मिक हस्तियों से मुलाकातें शामिल हैं) का मुकाबला करना भी है। पार्टी के भीतर असंतोष की खबरों के बीच, कार्यकर्ताओं में नया उत्साह पैदा करना भी इस मुहिम का एक उद्देश्य है।

राजनीतिक विश्लेषक इस प्रयास को, राजनीतिक नैरेटवि को फिर से सैट करने की कोशिश के रुप में देखते हैं। इसके जरिए वे समाजवादी पार्टी के पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) अभियान के सामने एक संस्कृतिक -राष्ट्रावादी एजेंडा बनाए रखना चाहते हैं। ज्ञातव्य है कि पीडीए अभियान ने भाजपा के व्यापक हिंदू एकजुटता के आधार को चुनौती दी है।

अखिलेश यादव ने धार्मिक मामलों में मौर्य की साख पर सवाल उठाकर मथुरा के इस अभियान का जवाब देने की कोशिश की है। उन्होंने भाजपा पर "धर्म" से ऊपर "धन" को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया है और राम मंदिर के लिए मिले चंदे में कथित अनियमितताओं को उजागर किया है। उन्होंने पीडीए अभियान जारी रखते हुए समाजवादी पार्टी को सनातन धर्म के रक्षक के रुप में पेश किया है। साथ ही, उन्होंने अयोध्या और वृंदावन सहित, विभिन्न धार्मिक स्थलों के दौरों पर जाने के संकेत भी दिए हैं।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंभाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- प्लाट नम्बर H1-4, इन्डस्ट्रीयल एरिया फैस प्रथम, जालौर, (राज.) फोन नम्बर 226422, 226423, जालौर। फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908